



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904

No. 168]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वाणिज्य मंत्रालय  
आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 45-आई० टी० सी० (पी० एन ) /82

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1982

विषय :—येन 1.8 बिलियन की ओ ई सी एफ ऋण समझौता सं०  
आई डी० पी० -18 के अधीन (बम्बई उप-नगरीय रेलवे प्राधु-  
निकीकरण परियोजना) माल और सेवाओं के आयात के लिए  
लाइसेंस शर्तें ।

मिसिल सं० आई पी सी/23(33)/82- बम्बई उप-नगरीय रेलवे  
प्राधुनिकीकरण परियोजना का लागू करने के लिए येन 1.8 बिलियन के  
ओ ई सी एफ ऋण समझौता सं० आई डी० पी० 18 के अधीन माल और  
सेवाओं के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस जारी करने के लिए जैसी शर्तें  
इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे सूचना के  
लिए अधिमूर्धित की जाती हैं ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,  
आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 45-आई टी सी (पी एन)/  
82 दिनांक 18 सितम्बर 1982 का परिशिष्ट ।

जापान की विदेशी आर्थिक सहायता निधि (आई ई सी एफ) द्वारा  
प्रदान किए गए 1.8 बिलियन येन ऋण के अधीन बम्बई सूबर्बन रेलवे  
प्राधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल के आयातों और  
सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें ।

खंड 1- सामान्य शर्तें

1(1) बम्बई सूबर्बन रेलवे प्राधुनिकीकरण परियोजना की आवश्यक-  
कताओं के वित्त-दान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि  
(आई ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 1.8 बिलियन येन का ऋण  
विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन  
अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और प्रनुबन्ध-1 की  
सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । ये देश इस ऋण  
के अन्तर्गत प्राप्त खोन देश होंगे ।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्ही मदों और उसी मूल्य के लिए  
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा निदेशालय, तकनीकी  
विकास/पूजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से किसी निकासी कर दी  
गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सो) का  
मूल्य 2,000 मिलियन (मायन-बीमा-भाडा) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रुप में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई मार्च-जनिक सूचना सं० 78/आई टी सी (पी एन) / 74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस से संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन" ऋण सं० आई० डी० पी०-18 होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जे० एन०" कोड होगा। भारतीय रेलवे को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में इसे दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जाती चाहिए।

1(3) लागत-सीमा-भाड़ा के आधार पर केवल भारतीय रेलवे के नाम से लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) भारतीय रेलवे की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 2,000 मिलियन (लागत-सीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(9) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि भारतीय रेलवे द्वारा आवेदन करने पर 31.12.86 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से सम्बन्धित माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, तक प्रतिबधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेवण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपय में किया जाता चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इस लिए लाइसेंस पर ही प्रसारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध -1 में उल्लिखित शेषों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-सीमा-भाड़ा के आधार पर किए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में किया जाएगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संधिदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते, इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सख्त लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनो पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी

होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुरन्त रूपया जमा करने की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोत लदान पर अवग-भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोत लदान वस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने परन्तु अधिक से से अधिक ..... के अंत तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निर्धारित करने से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31.12.1986 के बाद की न हो।

खंड-2 संभरण ठेके का सम्भालना करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त नि शुल्क मूल्य येन में (येन को भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपय में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेदन केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खूली अंतर्राष्ट्रीय संधिदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :-

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनकी इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोन्माहित हो जाए।

(ग) बोली खल जाने के बाद अनुफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(13) जिन मामलों में औपचारिक खूली अंतर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रिया विधि अपनाएगी :-

(क) जहां आयातक के पास विश्वमनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखा हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल घनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से विलक्ष्मी न ले या औपचारिक खूली अंतर्राष्ट्रीय संधिदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहाँ निधि औद्योगिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में, निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिसमें जहाँ तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औद्योगिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके।

- (1) औद्योगिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।
- (2) औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।
- (3) एक सभरक से सीधा क्रय विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली बोलियों के।

भारतीय रेलवे का ऋण करार तब किए जाने के तत्काल बाद ही निधि प्रो० ई० सी० एफ० को इसकी पुनरीक्षा के लिए बोलीकारों के लिए सभी नोटिफा और अनुदेशों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित सविदा, विनिर्दिष्टकरण और ड्राइंग, बोली विश्लेषण की रिपोर्ट, एवार्ड के लिए प्रस्ताव, और बोली से संबंधित अन्य सभी सगत दस्तावेज भेजेगा। प्रो० ई० सी० एफ० को दस्तावेज भेजने के लिए, ये दस्तावेज दो प्रतियों में भवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग को भेजे जाए।

2(4) विदेशी सभरक का भुगतान, उनके नाम भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए प्रो० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी० 18 के अधीन होने पर अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसका व्यौरा नीचे खंड-6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही सविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक सविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

## 2 (6) सभरक की पात्रता

सभरक पात्र स्त्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्त्रोत देशों में समाविष्ट और पंजीकृत व्यापिक व्यक्त है और पात्र स्त्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

## 2 (7) सविदा में घोषणा

प्रत्येक सविदा में सभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा —

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सभरक किया जाने वाला माल में (पात्र स्त्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आपात स्त्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है —

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{सभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य}} \times 100$$

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि (पात्र स्त्रोत देश का नाम) में (कामों का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्त्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

## 2 (8) अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमोद प्राप्त

जिन वस्तुओं में अपात्र स्त्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है, उसका वित्त खान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सभरक आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो —

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{सभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य}} \times 100$$

## खण्ड - 3 सभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) सभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए —

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहायता निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) के बीच बम्बई सबर्बन रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई० डी० पी० 18 (परियोजना सहायता) से संबंधित 14 मई 1982 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहायता निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) सभरक को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहायता निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) के बीच येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी० 18 से संबंधित 14 मई 1982 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी सभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा तो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और प्रो० ई० सी० एफ० द्वारा येन ऋण के अधीन अर्पित हो।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियाँ में)।

3(2) यदि किसी मामले में सभरक जापान में स्थित हो तो सभरण सविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी सभरक भारतीय रूपाय, टोकियो के परामर्श पर पौन परिवर्तन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय रूपाय, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम में अवगत कराएगा। और पौन-व्ययन कम से कम 4 महीने पूर्व भारतीय रूपाय को सूचना देगा, जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी सभरक को प्रत्येक पौन-व्ययन के पश्चात् आवश्यक व्यय देने हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय रूपाय, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

## खण्ड-4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (प्रो० ई० सी० एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय रेलवे और विदेशी सभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियाँ जो विदेशी सभरक द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियाँ सगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियाँ सहित जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रिया विधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आयोगों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग बम्बई सुबर्बन रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई०डी० पी०-18 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) की संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

#### खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साख-पत्र क्रिया-विधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा ओ०ई०सी०एफ० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद भारतीय रेलवे को सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी०ए० ए० एंड ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू० सी० ओ० बैंक ब्रिडिंग, संवर मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी०ए०ए० एंड ए० अनुबन्ध-4 के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबन्ध-6 (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए जारी करेगा। प्राधिकार पत्र की प्रतियाँ (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबन्ध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साख-पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी०ए०ए० एंड ए० में प्राधिकार पत्र के आधार पर साख पत्र खोलने के लिए उद्भूत क्रिया विधि सविधा संशोधन या अन्यथा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक करने बैंकों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र को खोलने रख-रखाव और परिकालन पर किए गए सभी खर्च विदेशी संभरक या आयातक के लेखे में जाएंगे। अतः भारतीय बैंक, टोकियो संभरक बैंक या आयातक से सभी खर्च प्राप्त करेगा, दस्तावेजों को सम्भाल के रखने और मोल-नोल करने और अन्य आकस्मिक खर्च भी संभरक/आयातकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरक को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ओ०ई०सी०एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का व्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 2.5-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास जापान द्वारा व्याज भुगतान पर किया गया खर्च भारतीय रेलवे [खंड 6(4)] से प्राप्त किया जाएगा।

#### खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंक को पराक्रम जहाजरानी

दस्तावेज भेजेगा और बैंक इसके बखते में यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, लीम हजारी, दिल्ली से रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये सार्वजनिक सूचना सं०-74 आई०डी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किया जाए।

आयातक आयातित माल का विवरण संभरक को विदेशी मुद्रा में भुगतान के समतुल्य रुपया निक्षेप करने के पश्चात् केवल बैंक से प्राप्त किए गए मूल लघान दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् करेगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अप्रतार्यी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109 आई०डी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई०डी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्धारित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस लेखा शर्ष में उद्भूत रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एंड एक्वासिज-843 मिजिल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परबेजीज एटस्ट्रा एन्ड एक्वासिज यन्डर क्रेडिट्स/लोन एग्ग्रीमेंट" लोन फोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 1.8 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई०डी०पी०-18 फार बम्बई सुबर्बन रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या जो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली मेथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, लीम हजारी, दिल्ली से सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई०डी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई०डी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 24-10-1968, सं० 132-आई०डी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई०डी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई०डी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होता चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबंध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरने समय आयातक/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई०डी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कायम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे" में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक की भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साधन देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रूपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एंड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की सूची त्रिनिमय नियंत्रण प्राप्ति पर गपया निक्षेप की धनराशि का पुष्ठाकल करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

भारतीय वृतावास, टोकियो द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को व्याज खर्च आदि के संबंध में येन के समतुल्य रूप से किए गए भुगतान की गणना भी उपर्युक्त खंड 6 की कड़िका 6 (1) में निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी। मुख्य लेखा अधिकारी, विदेश मन्त्रालय, नई दिल्ली के नाम में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी० ए० एंड ए० उचित अनुदेश जारी करने रहेंगे।

#### खंड-8 विविध व्यवस्थाएं

##### 8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोत-सदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, समद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

##### 8(2) सभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से सभरक को भ्रवगत करा देना चाहिए जो मास के लाने से जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

##### 8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और सभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। सविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

##### 8(4) सविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) म० आई डी-पी-18 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान (ओ ई सी एफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या लाइसेंसधारी को मुख्य पालन करना होगा।

##### 8(5) प्रतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

##### 8(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग-वर्णन
3. अनुबंध-3 अधिकारपत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4 प्राधिकारपत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए)

#### अनुबंध 1

##### पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ० पी० ई० पी० से भिन्न विकासशील देश

##### 1 अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र  
मोरोक़ो  
तुनीशिया

##### 2 अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला  
बोत्सवाना  
वरण्डी  
कैमेरून  
केप वर्डी द्वीप समूह  
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र  
चाद  
कमरों द्वीप समूह  
कांगो राहियों का गणतन्त्र  
भूमध्य गिनी (1)  
इथोपिया  
गाम्बिया  
घाना  
गिनी  
ग्राइवरी कोस्ट  
केनिया  
लेसोथो  
लाइबीरिया  
मालागासी गणतंत्र  
मालावी  
माली  
मार्गिनेनिया मारीशस  
मुज़ाम्बिक  
नाइजर  
पुर्तगामी गिनी  
रियूनियन  
रोडे़शिया  
रवान्डा  
सेन्ट हेलेना और डेस (2)  
भासोटोम और प्रिन्सीपल  
सेनेगाल  
सिचलीज  
सियरा लिओन  
सोमालिया  
सुडान  
स्वाजी लैण्ड  
टेरी आफर्स और इस्सा  
टोगो  
यूगाण्डा  
तंजानिया संयुक्त गणतंत्र  
अपर वोल्टा  
जाइरे गणतंत्र  
जाम्बिया  
3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय  
बहामास  
बारबडोस  
बाहोस



बेरमुड  
कोस्टारिका  
क्यूबा  
डोमिनिकन गणतन्त्र  
एलसल्वेडोर  
ग्वाटे माला  
ग्वाटे माला  
हैती  
होण्डुरस  
जेमेका  
मार्टिनिका  
मैक्सिको  
नीदर लैण्ड एन्टिलीज  
निकार गुवा  
पनामा  
सेन्ट पियरो और मिक्वेलोन  
ट्रिनिडाड और टोबागो  
वेस्ट इण्डोज (शाखा) एसआई ई  
(क) सम्बन्धित राज्य (1)  
(ख) आश्रित (2)

#### 4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेंटीना  
बोलिविया  
ब्राजील  
चिली  
कोलम्बिया  
फास्का लैण्ड द्वीप समूह  
फ्रान्सीसी गिनी  
गुयाना  
पाराग्वे  
पीरू  
सूरिनाम  
उरुग्वे

#### 5. मध्य पूर्वी एशिया

बेर्लिन  
इजराइल  
जोर्डन  
लेबनान  
ओमान  
सिरिआई अरब गणतन्त्र  
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)  
यमन अरब गणतन्त्र  
यमन जनवादी डी० आर० (4)

#### 6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान  
बांगला देश  
भूटान

ब्राजील

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप सहित

चिली

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित

कोलम्बिया

असेन्शन, क्रिस्टन डा हन एक्सेसिबिलिस, वाइटसेल गाफ फाका लैण्ड

द्वीप समूह

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, ओरेरे क्यूराकओ साहा, सेन्ट युस्टासियस,

सेन्ट फ्रान्सीसी गिनी

मार्टिन (दक्षिणी भाग)

वर्मा  
भारत  
माल द्वीप  
नेपाल  
पाकिस्तान  
श्रीलंका

#### 7. सुदूर पूर्वी एशिया

बरुनी  
हांगकांग  
खमेर गणतन्त्र  
कोरिया गणतन्त्र  
लाओस  
मकाओ  
मलेशिया  
फिलिपाइन  
मिंगापुर  
नाइवान  
थाइलैण्ड  
तिमोर  
वियतनाम गणतन्त्र  
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

#### 8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह  
फिजी  
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप  
फ्रान्सीसी पोलिनेशिया (5)  
नीरू  
न्यू कलेडोनिया  
न्यू हेब्रिडिस इंसिसेम (ब्रा० और फो०)  
नियो  
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)  
पापुवा न्यू गिनी  
सालोमन द्वीप समूह (ब्रा०)  
टोंगा  
बालिस और फूतुना  
पश्चिमी समाला

#### 9. यूरोप

साइप्रस  
जिब्राल्टर  
ग्रीक  
माल्टा  
स्पेन  
तुर्की  
यूगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप समूह एटिगुवा, डोमिनिका, गेनाहा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफो) नेविस - एनियुला, सेन्ट लूसिया और सेन्ट विन्सेट
- (2) मुख्य द्वीप समूह - मोन्तेसेरात, सेमान, तुर्कस और कोर्कोस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह
- (3) अजमान, दुबई, फुजाइरा, रास अल खैमाह, शरजाह और उम अल क्वैन
- (4) अदन और विभिन्न मुलतनत और अमीरात सहित ।
- (5) सोसायटी द्वीप समूह (नाहिरी सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटु काम्बीअर ग्रुप और मार्किस द्वीप समूह ।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

## (क-2) श्री० पो० ई० सी० के सवस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया  
बोनिविया  
लिबियान अरब गणमन्त्र  
रोमान  
नाइजीरिया  
इक्वेडोर  
बेन्जुएला  
ईरान  
ईराक  
कुवैत  
कानार  
सऊदी अरब  
प्रबधावी  
इण्डोनेशिया

## अनुबंध 2

श्री० ई० सी० एक द्वारा व्यवस्थित परियोजना कृण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग वर्णन

## 1. विज्ञापन :

श्रीपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संबंधित बोली आमंत्रित करने के लिए श्रुणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कान से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए।

## 2 बोली के बस्तावेज और सविदाएं

## 2.1 बोली बांड और गारंटियां

बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन, इनको इतना कठिन नहीं बनाना जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साहित हो जाए। बोली खोलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बीबी बांड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

## 2.2 सविदा की शर्तें :

सविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई सविदा की शर्तों में भ्रायातक और ठेकेदार या सभरक के अधिकार और शक्ति और यदि भ्रायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उनके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होते चाहिए। सविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है, के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

## 2.3 सविदाओं की किस्म और प्रकार :

सविदाएं, निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या अ बेदिन मदों के या एक मुश्त कीमतों के या सविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है या और बोली लगाने वाले बस्तावेजों में खुली गई सविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित सविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, निधि को स्वीकार्य नहीं हैं।

इंजीनियरिंग, उपकरण और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल सविदाएं (उनकी सविदाएं) यदि श्रुणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करे तो वे स्वीकार्य हैं।

## 2.4 पात्र सभरक

वे नियमित या सभरक जितने माल एवं सेवाओं का विस्तार श्रुण को रकम में से किया जाता है (जिसे इसके बाद 'पात्र सभरक' कहा गया है), पात्र खोन देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :—

- (1) अभिवात किए गए शेरों का एक बड़ा भाग पात्र खोन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र खोन देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे न्यायिक 'व्यक्तियों' का पंजीकरण पात्र खोन देश में होगा।

## 3. सविदा की कीमत :

- (क) सविदा की कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि सविदा की कीमत का वह भाग जो ठेकेदार श्रुणी के देश में खर्च करेगा श्रुणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

## (ख) मूल्य समझन धाराएं :—

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि वस्तु कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली का कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है।

यदि सविदा के प्रमुख लागत अवधारकों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो सविदा को कीमतों में समझन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समझन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में संसाफ परिभाषित होना चाहिए।

माल की सप्ल ई के लिए सविदाओं में कीमतों के समझन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मितिल कायों के लिए सविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा का प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्दे किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समझन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए।

ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उदायो के परिचय का आभाम नहीं करती हैं जिनके द्वारा सविदा मूल्य समझन तिरा जा सके।

## 4. बीमा :

सकल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमा की किन्हीं का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित सविदा या विदेशी सभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी सभरक को दिया गया है, या इनकी फाटी प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक सविदा में सभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जायेगा :—

'मैं (हम) एतद् द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र सभरक है, क्योंकि शेरों का ..... प्रतिशत (%) ..  
..... (पात्र स्त्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, और ..... प्रतिशत ( )  
निदेशक ..... (पात्र खोन देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी कंपनी) ..... (पात्र खोन देश) में पंजीकृत कराई गई है।

#### 4.1. मापदंड

यदि उन राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माप है, तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाता चाहिए कि आपत औद्योगिक मापदंड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदंडों की कठिने के बराबर या इससे अधिक मापदंड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

#### 4.2. बाण्ड नामों का प्रयोग :

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्तों की आवश्यकता है य यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विषयनामों को बनाए रखने के लिए सामकीकरण की एक शिरी की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल खड, नाम, सूची, संख्या या विशेष चिह्नों के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाण्ड वाले सामन में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य-वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उत्तम हैं।

#### 4.3. गारंटी निष्पादन बाण्ड और रोक रखी गई धनराशि :

सिविल कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बाण्ड द्वारा हो जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अर्पणित बाण्ड की धनराशि को बोली दस्तावेज में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बाण्ड की अर्पणा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मचना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बाण्ड चुना जाता है तो वह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

#### 5. चुकाई जाने वाली शर्त :

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या संपूर्णता में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली शर्त से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब समय से पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोतल देने के लिए भी व्यवस्था की जाए।

#### 6. बाध्यकारी परिस्थितियां :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए इस संबंध में धाराएं होनी चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अर्पण वास्तवों को न पूरा करना उस ह्रास में एक चुक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चुक विवश करने वाली स्थितियों में फॉर्स मज्योर के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जाती है)।

#### 7. शर्तों का निपटारा :

शर्तों के निपटारे से संबंधित व्यवस्था संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए समझौते और मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध नर या अन्य ऐसी व्यवस्था जो अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्गत और विरुद्ध सारक दोनों का प्रतिकार्य हो, पर आधारित होने चाहिए।

#### 8. बोली की व्याख्या :

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लयी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

#### 9. बोली खोलना, सुश्रूयक और ठेका देना :

##### 9.1. बोलियों के प्रामाण्य और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय :

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा को सहजता और वेबोदगी पर निर्भर करेगा। मध्यम अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होता चाहिए।

##### 9.2. बोली खोलने की किया चिधि :

बोलियों की अन्तिम पावनी के लिए और बोली खोलने के लिए नियम, समय और स्थान को बोली प्रामाण्य में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही खोटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोलीकार और किता वैकल्पिक बोलियों को कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उनको रिफाई कर लेना चाहिए।

##### 9.3. बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन :

बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली खोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोली के मूल तत्व में कोई परिवर्तन लाए बिना ही केवल स्पष्टीकरणों का ही स्वीकार किया जाये। अन्तर्गत किसी भी बोली खोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के साराण एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

##### 9.4. गुप्त रखी जाने वाली क्रियाचिधि :

कानून द्वारा यथा अर्पणित की छोड़कर बोली को खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाचिधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

##### 9.5. बोलियों की जांच :

बोलियों के खोलने के बाद हमका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं निज दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विविध हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलिया सामान्यतः अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलिया मूल रूप से विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं है या उनमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली सम्बन्धी दस्तावेजों के अनुसार नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलावट के लिए तकनीकी विवेक किया जाना चाहिए।



## 9.6 बोलीकार की पूर्ण योग्यताएँ :

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय कर कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध सविदा को प्राप्ती रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उस योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को प्रस्वीकार कर दिया जाता चाहिए।

## 9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान :

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली की कीमत के प्रतिनिधित्व अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता का विचार में लिया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो वे बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदंड के अनुसार रूप से की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए यदि धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा प्रथम मुद्राएँ जिनमें मुख्य चुकाने का प्रस्ताव किया जाता है तो बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की दर सरकारी कोट द्वारा प्रकाशित विनियम दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियाँ चुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिमूर्चित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

## 9.8 बोलियों को प्रस्वीकृत करना :

बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियाँ को प्रस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को प्रस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयत्नार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियाँ प्रामाणित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को प्रस्वीकार करने के लिए भी जब अधिसूचना देने चाहिए जहाँ—

(क) बोलियाँ, बोली दस्तावेज के प्राणय के अनुसार नहीं है, या

(ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को प्रस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उस कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे प्रस्वीकृति मिट्ट की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिणाम पर (या बोलियों के लिए मूल प्रामाणन में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी मतोषजनक सविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सीदा कर सकता है।

## 9.9 सविदा का निर्णय

सविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चय की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिणामित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

743 GI/82—2

## अनुसूच 3

आधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र

संख्या .

दिनांक .

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा पत्रीक्षा निदेशक,

वित्त मंत्रालय,

प्राथमिक कार्य विभाग,

पू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय --वेन कोडिट सं० आई० डी० पी०-18 (परियोजना, सहायता)  
1979-80 के प्रत्यर्जन प्रदान में . का प्राधान्य।

महोदय,

उपर उल्लिखित वेन कोडिट सं० आई० डी० पी० 18 (परियोजना सहायता) के अधीन . . . . . से . . . . . के प्राधान्य के संबंध में . . . . . (बैंक का नाम) . . . . . जो कि वही होता चाहिए जो नीचे (ड) में समझ समुदाय संरक्षक के नाम में मात्र पत्र कोलने के लिए दिया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित शर्तों प्रस्तुत करने हैं --

(क) भारतीय प्राधान्य का नाम और पता।

(ख) प्राधान्य लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तरीका जिस तक वेध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके . . . . . क्या वह सीधे रूप या औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या सविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) मान का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) मान का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इनर खोल देशों से प्राधान्य संरक्षकों का प्रतिफल।

(छ) सविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (वेन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (वेन में)।

(झ) वार्षिक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (वेन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुदाय के संरक्षकों के साथ की गई सविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुदाय के संरक्षक का नाम और पता --

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र खोल देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए क्षेत्रों का प्रतिफल।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संरक्षक का निवास स्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिफल जो पात्र खोल देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित निविदाओं जिनको सविदा के प्रत्यर्जन भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दी की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

- (इ) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो का भुगतान करने समय प्रस्तुत किए जाने वाले वस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटारा दिखाने हुए)
- (ण) पातलदान अनुदेश (आवनाम्नरण/पार्ट शिपमेंट को अनुमति दी गई है या नहीं निविष्ट कीजिए)
- (न) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (य) क्या उमी लाइसेंस का अन्तर्गत संचिता (संचिताए) का दो गई है और जापानी प्राधिकारियों का अधिसूचित कर दी गई है, यदि हा तो ऐसी प्रत्येक संचिता की संख्या दिनांक और मुख्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ क्रिये अन्तर्गत अ ई० सी० एफ० का इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबंध 4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

सं० एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

प्राधिकार कार्य विभाग

आई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय - येन केडिट (परियोजना सहायता) ऋण करण सं० आई० डी० पी०-18 के अधीन आयात साख्यपत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपने बैंक के साथ 25.3.1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एनडू द्वारा यथा संभव ब्योरे के अनुसार सर्वश्री के नाम से

येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साख्यपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साख्यपत्र की प्रति आयातक के बैंक अ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और हम पुष्ठांकित की जाए।

साख्यपत्र की शर्तों के प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के बाद अ० ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरकों को आपक द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और अ० ई० सी० एफ० द्वारा उनकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए चुकाए जाने योग्य प्रसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सम्बन्ध बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे की प्रभावित किए बिना किया जाएगा। बैंक के द्वारा खर्च जिसे साख्यपत्र खोलने, रख रखाव करने और साख्यपत्रों का जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल है क्योंकि वे भी परकाय्य दस्तावेजों के संभालन से संबंधित है और यदि कोई हा तो, विदेशी संभरकों के बैंकरो के खर्च भी विदेशी संभरकों को ही देने पड़ेगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों

की प्रतिपूर्ति का दावा अ० ई० सी० एफ० से नहीं किया जा सकता जब और जैसे ही आपके द्वारा भुगतान किया जाता है और आपके प्रतिपूर्ति की जाती है, तो निश्चित प्रपत्र में हम संभाव्य का सूचना भेजे।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम से साख्यपत्र खोलने के लिए है। इस सम्बन्ध के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकार के मद्दे खोले गए और के नए साख्यपत्र या साख्यपत्र में बाद के समझौतों का अनुपातन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र तब वैध रहेगा।

सन्दीप,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित

1 आयातक को उनके पत्र में दिनांक के संबंध में।

2 आयातक का बैंक

उत्तरे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो जांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रपता जमा करने की व्यवस्था करे। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रपत की गणना सार्वजनिक सूचना सं० आई० डी० सी० (पी एन)/76- दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई० डी० सी० (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 243-आई० डी० सी० (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132-आई० डी० सी० (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० डी० सी० (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई० डी० सी० (पी एन)/76, दिनांक 13-10-76 को शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा पीछे जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपॉजिट एंड एडवांसिज-34.3-सिविल डिपॉजिट-डिपॉजिट फॉर परचेजिज एटसेकट्टा एन्डर अन्डर परचेजिज केडिट अन्डर लोव एग्रीमेंट येन 18 विलियम येन केडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी०-18 फॉर 1979-80 प्रॉस वी गवर्नमेंट ऑफ जापान है।

जिन मामलों में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई० डी० सी० (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार तकद जमा किया जाता है, उनको चालान का मूल रूप में एक प्रति बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए प्रत्येक-पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी -

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय (प्राधिकार कार्य विभाग)

पहली मजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,

संभव मार्ग, नई दिल्ली-110001।

जिन मामलों में मुख्य रूप से ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 से यथा उल्लिखित वर्गीकृत हुण्डी द्वारा प्रेषित करता है उनका सूचना उक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए मुख्य रूप का पूरा ब्योरा इन विभाग की भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चों, व्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्च (जिसमें विदेशी सभरकों के बैंकरों के खर्चों भी शामिल हैं) प्रमुख सेवा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समनुव्य रूप प्रवा करने पर ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, इस विभाग द्वारा उचित मलाई बैंक आफ इंडिया, टोकियो / भारतीय वृत्तावास, जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3 निदेशक ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि टेकू-बसी स्पूडो बिन्डिंग, 4-1 टोहितोमेजी 1, कोमे, शिमोडा-कू टोकियो-100 जापान।

4 भारतीय वृत्तावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

(प्रो० ई० सी० एफ० एम० सी० 1 प्रवक्त)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(मान के लिए लागू)

सेवा में,

दिनांक

यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं० \_\_\_\_\_ के दिनांक \_\_\_\_\_ के अनुसरण से जारी किया गया है।

मिय सहोषय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निहायने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए अपनी छुट्टी द्वारा उपलब्ध रहत यः रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० \_\_\_\_\_ खोल दिया है जो \_\_\_\_\_ येन (-----) येन (-----) कह सकते हैं, जो कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित वस्तावेज के साथ भेजा जाना है :-

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

कलस घान बोर्ड समुद्री पोत लक्षन बिल जिसमें दिए गए प्रावजों का पूरा सेट हो। अन्यक पुष्ठांकित एब विहित 'फोट' एवं 'नोटिफाइड'.

अन्य दस्तावेज जिसमें ----- से -----

तक लक्षन का न्यापन दिया गया हो (सविदा सं० -----) (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आशिक पोतलक्षन स्वीकृत है। वाहानान्तरण ----- स्वीकृत है।

पोतलक्षन बिल जो ----- से बाब को निधि का नहीं होता चाहिए। आवेशितों को डाफ्ट ----- 19- तक आवश्यक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी डाफ्ट और दस्तावेजों पर यह धनक होता चाहिए। 'अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ----- दिनांक ----- 19- के अन्तर्गत निरसनवाया गया और प्रायतन सर्वसं० (संख्याएँ) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।'

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करते निकलवाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशों का दस्तावेजों का मूर्तगो पर विविधन स्वाक्षर किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विचार पूर्वक न बनाया जाए कि क्रेडिट "युतिकार्म" कस्टम एंड प्रेक्टिस फार इन्कॉर्पोरेटड क्रेडिटर्स (1974 रिजिजन) इन्टरनेशनल बैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290 के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्याख्याओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अर्द्धों के अनुसार छुट्टी को धनराशि का लोटा देगे।

2 सौदा करने वाले बैंक को यह बताने हुए हमें डाफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रतान पत्र अथवा भेजत चाहिए कि शेष वस्तावेज सीधे ही हमें डाफ्ट द्वारा ----- की भेज दिए गए हैं।

3. क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्च आयातकों/प्राप्तकों के लेखों के लिए है।

भवर्धय

(-----)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा -----

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें:

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं० ----- का अधिकतम है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ----- येन, जो कि कुल सविदा मूल्य का ----- प्रतिशत है।

अपेक्षित वस्तावेज.

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2 मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ----- येन

जो कि कुल सविदा मूल्य का ----- प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलक्षन दस्तावेजों के मंहे भुगतान:

धनराशि ----- येन

सविदा की कुल मूल्य का ----- प्रतिशत।

टिप्पणी—पोतलक्षन दस्तावेजों के मंहे पूर्ण भुगतान के मामले में इस सलसल दस्तावेजों का आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध-6

प्रवक्त प्रो० ई० सी० एफ० एम० सी० 2

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में,

दिनांक -----

यह साख पत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं० ----- के दिनांक ----- के अनुसरण से जारी किया गया है।

प्रिय सहोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण धीरे धीरे के लिए लाभकारी डाफ्ट एंड माइट द्वारा उल्लेख्य रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अनिवार्यता माहिर सं० खोल दिया है जो येन—

(येन—पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा सं० और परियोजना) के संबंधित दस्तावेजों को तय्यी करना है। सोदा तय करने के लिए डाफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी डाफ्ट और दस्तावेज "अपरिवर्तनीय साक्ष्य सं०" के दिनांक के अन्तर्गत भुना दिए गए हैं" से चिह्नित होने चाहिए।

यह केबिड हस्ताक्षरणीय नहीं है।

हम एल० द्वारा बचन देते हैं कि इस केबिड के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और अतिरिक्त को दस्तावेजों की सुपुर्गों पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह केबिड "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाक्यूमेंटरी केबिड्स (1974 रिबीज) इंडरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स बोर्ड नं० 290" के अधीन है।

सोदा करने वाले बैंक को विशेष धन देना :-

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (जहाँ और इसके मनोनीत प्राधिकारी, द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस केबिड के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाय वास्तविक विवरण का आवश्यकता है।

2. उपर उल्लिखित ज्ञान समझने के अधीन जारी किए गए बचन-बढ़ता पत्र के उपबंधों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम डाफ्टों की धनराशि को मान-सोस करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का बचन देते हैं।

3. उपर्युक्त पत्र 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और 1 में 1 में 1 की प्रति के तुरन्त बाद ही दी जाएंगे।

4. इस साक्ष के अन्तर्गत बैंक के सभी बचन धायातकों/संभरकों के बीच के लिए है।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे माहिर सं० का एक अभिन्न भाग है।

1. प्रारंभिक भुगतान  
धनराशि  
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज, लाभकारी विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. भुगतान धृष्टि

संपूर्ण योग की धनराशि  
कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत  
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है :-

येन धनराशि धनित भुगतान तिथि

येन येन

पहली किस्त येन

दूसरी किस्त येन

...

अपेक्षित दस्तावेज, (जहाँ अधिकांश उमके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

संदर्भ सं०

मेका सं०,

(संभरक का नाम और पता)

मेकम ज्ञान करार सं० के अन्तर्गत परियोजना में संवर्धित के नाम में येन के लिए द्वारा जारी किए गए साक्ष पत्र की सं० दिनांक

में अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि (जहाँ) एवमुद्रारा और के बीच संविदा सं० दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्र पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा की धनराशि (येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है।

(...)

(जहाँ)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष धन देना :-

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्ज्या जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE  
IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 45—ITC (PN) 82

New Delhi, the 18th September, 1982

SUB : Licensing conditions for import of goods and services under OECF loan agreement No. ID-P. 18 of Yen 1.8 billion (Bombay sub-urban Railways Modernisation Project).

File No. IPC/23 (33) 82.—The terms & conditions governing the issuance of import licence in respect of goods & services under OECF loan Agreement No. I.D.-P.18



of Yen 1.8 Billion for the implementation of the Bombay Suburban Railways Modernisation Project, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE  
PUBLIC NOTICE NO. 45-ITC (PN)/82,  
dated, the 18th September, 1982

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF  
GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF  
YEN 1.8 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF  
THE BOMBAY SUBURBAN RAILWAYS MODERNIZA-  
TION PROJECT EXTENDED BY THE OVERSEAS ECO-  
NOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN

Section I—General conditions

I (i) The Yen Credit of 1.8 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Bombay Suburban Railways Modernization Project is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I. (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/OG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed 2,000 million (CIF).

The rupee value of the Import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 18". first and second suffix licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to the Indian Railways, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of the Indian Railways on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of the Indian Railways more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed 2,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by the Indian Railways, be granted upto 31-12-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas Supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on

Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1 (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of ....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-86.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude India Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

- Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited.



(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it in appropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate:

- (i) Formal Selective International Tendering.
- (ii) Informal International Competitive Procurement.
- (iii) Direct Purchases from a single supplier.

The Indian Railways shall submit to the Fund (OECF) immediately after conclusion of the Loan Agreement for its review copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposal for awards, and all other documents relevant to the bidding. These documents may be forwarded to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, in duplicate, for onward submission to the OECF.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.18 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

#### II(vi) Eligibility of Supplier.

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

#### II(vii) Declaration in Contract.

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in \_\_\_\_\_ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that \_\_\_\_\_ (Name of Company) has been incorporated and registered in \_\_\_\_\_ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries"

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent

(30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae:

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

#### Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract:

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 14th May, 1982 concerning the Yen Credit No. ID-P.18 (Project Aid) for Bombay Suburban Railways Modernization Project and will be subjected to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.18 dated 14th May, 1982 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply of contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the imported after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

#### Section IV—Contract Approval by OECF.

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both Indian Railways and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.18 (Project Aid) for Bombay Suburban Railways Modernization Project.

#### Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, Indian Railways and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the Indian Railways should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building,

Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas supplier concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the Letter of Credit will be either to the account of overseas suppliers or the importer. B.O.I., Tokyo, will therefore, recover all these charges from the suppliers' Bank or the importer, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers/importer.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/O Finance) on 25th March, 1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the Indian Railways vide Section VI (iv) infra.

#### Section VI—Responsibility for rupee deposit.

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974.

The importer will take delivery of the imported goods only after producing the original shipping documents obtained from the Banker after depositing the rupee equivalent of the foreign currency payment made to the supplier. Permission of the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi should be obtained for any departure from this procedure. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in public Notice No. 102-ITC (PN)/74 dated 3rd August 1974 and No. 8-ITC (PN)/76 dated 17th January, 1976 or as may be notified by Government from

time to time through Public Notices of the CCI & E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "Rupee Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements" Loans from the Government of Japan—1.8 Billion Yen Credit No. 1D-P.18 for Bombay Suburban Railways Modernization Project. The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974, will however, not be applicable as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30th August, 1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24th October, 1968, No. 132-ITC (PN)/71 dated 5th October, 1971 No. 74-ITC (PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12th October, 1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5th October, 1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans:—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA & A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA & A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo to B.O.I., Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA & A will be issuing suitable advices.

#### Section VIII—Miscellaneous provisions.

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

## VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

## VIII(iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

## VIII(iv) Future Instructions.

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 18 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

## VIII(v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

## VIII(vi) List of Annexures.

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

## ANNEXURE I

## LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

## A Developing Countries and Territories

## (a1) Non-OPEC Developing Countries

## I. AFRICA, North of Sahara

Egypt  
Morocco  
Tunisia

## II. AFRICA, South of Sahara

Angola  
Botswana  
Burundi  
Cameroon  
Cape Verde Islands  
Central African Rep.  
Chad  
Comoro Islands  
Congo, People's Republic of  
Dahomey  
Equatorial Guinea (1)  
Ethiopia  
Gambia  
Ghana  
Guinea  
Ivory Coast  
Kenya  
Lesotho  
Liberia  
Malagasy Republic  
Malawi  
Mali  
Mauritania, Mauritius  
Mozambique  
Niger

Portuguese Guinea  
Reunion  
Rhodesia  
Rwanda  
St. Helena and Dep (2)  
Sao Tomo and Principe  
Senegal  
Seychelles  
Sierra Leone  
Somalia  
Sudan  
Swaziland  
Terro. Afars and Issas  
Togo  
Uganda  
Un. Rep. of Tanzania  
Upper Volta  
Zaire Republic  
Zambia

## III. AMERICA, North and Central

Bahamas  
Barbados  
Belize  
Bermuda  
Costa Rica  
Cuba  
Dominican Republic  
El Salvador  
Guadeloupe  
Guatemala  
Haiti  
Honduras  
Jamaica  
Martinique  
Mexico  
Netherlands Antilles  
Nicaragua  
Panama  
St. Pierre & Miquelon  
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Fustic, St. Martin (Southern part).

## America, North &amp; Central

## West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

## IV. AMERICA, South

Argentina  
Bolivia  
Brazil  
Chile  
Colombia  
Falkland Islands  
French Guiana  
Guyana  
Paraguay  
Peru  
Surinam  
Uruguay

## V. ASIA, Middle East

Bahrain  
Israel  
Jordan  
Lebanon  
Oman  
Syrian Arab Republic  
United Arab Emirates (3)  
Yemen Arab Republic  
Yemen, People's D.R. (4)

## ANNEXURE-II

## VI. ASIA, South

Afghanistan  
Bangladesh  
Bhutan  
Burma  
India  
Maldivis  
Nepal  
Pakistan  
Sri Lanka

## VII. ASIA, Far East

Brunei  
Hong Kong  
Khmer Republic  
Korea, Republic of  
Macau  
Malaysia  
Philippines  
Singapore  
Thailand  
Thailand  
Timor  
Viet-Nam, Rep. of  
Viet-Nam Dem. Rep.

## VIII. OCEANIA

Cook Islands  
Fiji  
Gilbert & Ellice Is.  
French Polynesia (5)  
Nauru  
New Caledonia  
New Hebrides (Br. and Fr.)  
Niue  
Pacific Islands (US) (6)  
Papua New Guinea  
Solomon Islands (Br.)  
Tonga  
Wallis and Futuna  
Western Samoa

## IX. Europe

Cyprus  
Gibraltar  
Greece  
Malta  
Spain  
Turkey  
Yugoslavia

- (1) Main islands : Atigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands; Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member of Association Countries of OPEC :

Algeria  
Bolivia  
Libyan Arab Republic  
Gabon  
Nigeria  
Ecuador  
Venezuela  
Iran  
Iraq  
Kuwait  
Qatar  
Saudi Arabia  
Abu Dhabi  
Indonesia

743 GI/82—3

Main guidelines for procurement of goods and services under the Project Loans as formulated by OECF :

## I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India

## II. Bidding Documents and Contracts

## II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

## II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

## II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

## II-4. Eligible Suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions:—

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

## III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labours and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.



The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order of confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract :

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as \_\_\_\_\_ per cent (%) of the shares are held by nationals of \_\_\_\_\_ (eligible source country), and \_\_\_\_\_ per cent (\_\_\_\_\_) of the directors are nationals of \_\_\_\_\_ (eligible source country) and my (our) company has been registered in \_\_\_\_\_ (eligible source country)".

IV-1. Standards.—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money.—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V Liquidated Damage.—Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure.—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes.—Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which

have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation.—Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

#### IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids.—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be Confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders.—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower, if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made.



In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

**IX-8. Rejection of Bids.**—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

**IX-9. Award of Contract.**—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

### ANNEXURE III

#### Request for Issue of the Letter of Authority

No. DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Sub.—Import of from Japan under the  
Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) for 1979-80.

Sir,

In connection with the import of .....from.....under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the .....(name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier;
  - (i) Nationality.

- (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
- (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
- (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (1) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (including No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank of India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

### ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Yen Credit (Project Aid).—Loan Agreement No. ID-P. 18—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ favouring M/s. \_\_\_\_\_ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No. — dated —.

2. Importers' Banker—. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan 1.8 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 18 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

# ANNEXURE-V

Form OECF-LCI

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. —, dated — between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. — in your favour for account of — for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y — (Say yen ) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clear on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight"

and "Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. — (if any) from — to — Partial shipments are — permitted. Transshipment is — permitted.

Bills of lading must be dated not later than — Draft must be presented for negotiation not later than — All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under — irrevocable credit No. — dated and Import Reference No(s) — (if any)" This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall by duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :—

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to —
3. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By :

(Authorised Signature—)

## PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. —.

I. Initial Payment

Amount : Y —

being — % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

## II. Intermediate Payment (if any)

Amount : \_\_\_\_\_

being \_\_\_\_\_% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

## III. Payment against Shipping Documents

Amount : \_\_\_\_\_

being \_\_\_\_\_% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

## ANNEXURE-VI

### Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit  
(Applicable for Services)

To \_\_\_\_\_

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has  
been issued pursuant to

Loan Agreement No. \_\_\_\_\_

dated \_\_\_\_\_

between (Borrower) and THE  
OVERSEAS ECONOMIC  
COOPERATION ON FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. \_\_\_\_\_ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of \_\_\_\_\_ (Say Yen ) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. \_\_\_\_\_ with regard to \_\_\_\_\_ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than \_\_\_\_\_

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. \_\_\_\_\_ dated".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

### Special Instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours Faithfully,

(a commercial bank)

By : \_\_\_\_\_

(Authorized Signature)

### PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. \_\_\_\_\_

#### I. Initial Payment

Amount : Y \_\_\_\_\_

being \_\_\_\_\_% of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

#### II. Progress Payment

Agreement amount: Y \_\_\_\_\_

being \_\_\_\_\_% of the total contract price to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
_____	_____
_____	_____

1st Instalment : \_\_\_\_\_

2nd Instalment : \_\_\_\_\_

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date:

Ref. No.

To \_\_\_\_\_

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No. \_\_\_\_\_, dated

issued by \_\_\_\_\_

for Y \_\_\_\_\_ in favour of

\_\_\_\_\_ concerning \_\_\_\_\_ Project

under Loan Agreement No. \_\_\_\_\_

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle \_\_\_\_\_ to receive the sum of Y \_\_\_\_\_ (Yen \_\_\_\_\_) on from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

(Borrower)

By:

(Authorized Signature)

### Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

